खिल उठा बसंत...

जबलपुर। संस्कारधानी में बसंत ऋतु का ही असर है कि पेड़ों पर रंग-बिरंगे फूल खिल उठे हैं। इससे धूप की तपन जहां मुसाफिरों को ठंडक देती है तो वही मन प्रफुल्लित हो उठता है।

होली आ रही है...

संस्कारधानी समेत आसपास के जंगलों में पलाश खिल उठा है। शायद इन्हें भी आभास हो चुका है कि होली का त्यौहार नजदीक है। कुछ दिन बाद ही अब इनसे रंग बनेंगे और लोग होली खेलेंगे। कहीं दूर पलाश खिला हुआ हो तो दूर से ही चमक उठता है।

प्रदेश सरकार के बजट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं

भाजपा की नजर में विकास का बजट तो कांग्रेस ने बताया जुमले का पुलिंदा

हरिभूमि, जबलपुर।

मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2025 आ चुका है. मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार की ओर से बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार की ओर से काई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। टैक्स की सभी प्रक्रिया को पहले जैसा ही रखा गया है। फिलहाल यही इस बजट की सबसे बड़ी राहत दिखाई दे रही है. बजट आने के बाद से बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरु हो गया. जहां एक तरफ भाजपा ने इसे एतिहासिक बताया तो कांग्रेस की नजर में यह बजट सिर्फ कागजी जुमले बाजी का पुलिंदा है. वहीं व्यापारिक संगठनों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही।

सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है बजट : तोमर

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया गया। बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाये गये इस बजट में ग़रीब ,युवाओं, अन्नदाता और नारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वर्ष 37 हजार 734 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 10 हजार 343 करोड़ रूपए अधिक है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

लोक कल्याण के लिये सरकार संकल्पित : सिंह

पश्चिम विधानसभा से विधायक एवं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना के साथ मध्य प्रदेश के कोने कोने को जोड़ने का संकल्प साकार हो रहा है. उन्होंने कहा बजट में हर वर्ग के लिये प्रावधान और हर वर्ग के लिये राहत रखी गई है. यह एक ऐतिहासिक बजट है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में सड़कों का जाल बिछाकर आमजन के जीवन में समृध्दि लाने और उनकी यात्राओं सुगम सुरक्षित करने के लिये हम सभी संकल्पित है।

पूरे मध्य प्रदेश की उपेक्षा : घनघोरिया

जबलपुर पूर्व से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा ये बजट नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र, दलित, पिछड़े, आदिवासी अल्पसंख्यक व पूरे मध्य प्रदेश की उपेक्षा वाला बजट है. उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत करने की सिर्फ खाना पूर्ति की है. विकास, औद्योगिकीकरण, प्रदेश पर बढ़ता कर्ज और शिक्षा के लिये नाम मात्र के भी प्रावधान बजट में नहीं किये गये हैं।

समग्र विकास वाला बजटः अभिलाष पांडे

4 लाख 21 हजार करोड़ का बजट मध्य प्रदेश के जन नायक मुख्यमंत्री का विजन है. जिस तरह से विकास के माडल पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, समग्र विकास इस बजट के अंदर है. इसमें गरीब, युवा अन्नदाता नारीशक्ति के उत्थान की बात की है. कृषि अनुंसधान के साथ साथ रोजगार के बड़े प्रबंध है. हर विधानसभा में एक स्टेडियम की बात की गई है. समग्र विकास वाला बजट है.

जिले की उपेक्षा की गईः जबलपुर चेम्बर

जबलपुर चेम्बर ने इस बजट का संतुलित बजट बताया. चेम्बर अध्यक्ष प्रेम दुबे ने कहा जबलपुर क्षेत्र में औद्योगिकरण के विकास के प्रावधान न होना निराषा जनक है। जिले में प्रस्तावित वन प्रोडक्ट योजना जो मटर पर आधारित है वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के रुप में मटर के कलस्टर फोर्मेषन के लिए जबलपुर में कोई घोषणा नही की गई। चेम्बर अध्यक्ष प्रेम दुबे ने कहा कि मेट्रो टेन भोपाल और इंदौर के लिए घोषित की गई और जबलपुर से इसकी उपेक्षा की गई। नरिंदर पांधे द्वारा शहर को एक भी विष्वस्तरीय स्टेडियम और विश्वविद्यालय न मिल पाना निराशा जनक बताया गया।

सर्वहारा विकास का बजट : रोहाणी

केंट के भाजपा विधायक ईश्वरदास रोहाणी ने कहा है कि मप्र के मोहन सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवा, गरीब, किसान, और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए है।

प्रदेश का सर्वहितकारी बजट : सांसद

जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद आशीष दुबे ने बुधवार को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सरकार के बजट को हर क्षेत्र में सौगात देने वाला और मध्यप्रदेश को विकास की राह पर द्रुत गति से बढ़ाने वाला बजट निरूपित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश का संकल्प इस बजट के माध्यम से और सशक्त होगा।

महाकौशल पर फोकस नहीं : सेठी

केट के प्रदेश सचिव दीपक सेठी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र पर सरकार का ऐसा कोई विशेष बजट में प्रावधान नहीं देखा गया जबकि जबलपुर के आसपास टूरिज्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है टूरिज्म हब बनने से यहां पर एक फिल्म सिटी बनाई जी सकती है, जिस तरह की पूर्व में कई वर्षों से यहां कई सीरियस एवं कई फिल्मों की शूटिंग की जा रही है यह दर्शाती है कि यहां टूरिज्म को अत्यधिक बढ़ावा मिल सकेगा, शहर में तीन से चार पांच सितारा होटल आना भी एक बहुत अच्छा संकेत देता है,

किसानों के हक में 3 प्रतिशत हिस्सा आया : अग्रवाल

मध्य प्रदेश कृषक समाज के प्रांत अध्यक्ष इंजी. केके अग्रवाल ने कहा सरकार के इस वर्ष के बजट मे विगत वर्ष की तुलना मे 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। किसानों के हक मे इस बढ़ोत्री का 3 प्रतिशत हिस्सा ही आया है। गांव, खेत, किसान का बजट कुल बजट का 9 प्रतिशत है। जो हमारी 60 प्रतिशत आबादी के लिए अपर्याप्त है।

जमीनी हकीकत जानने निगमायुक्त पहुंची कठौंदा प्लांट

जबलपुर। निगमायुक्त मती प्रीति यादव स्वच्छ सर्वेक्षण की जमीनी हकीकत जानने अचानक कठौंदा स्थित लैंड फिल साईट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निरीक्षण करने पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष कार्यो को भी जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। निगमायुक्त मती प्रीति यादव ने सीवर प्लांट का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। निरीक्षण के समय उपायुक्त स्वास्थ्य संभव अयाची, स्वास्थ्य अधिकारी संदीप जायसवाल, सहायक नोडल स्वच्छता सेल अभिनव मिश्रा, संजय कुशवाहा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन यादव सी.एस.आई. सौरभ आदि उपस्थित रहे।

रानीताल क्षेत्र के समीप कचरे डंपिग साइट पर बनेगा सिटी लेवल पार्क

जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में रानीताल तालाब के समीप कचरे के उपरांत रिक्त होने वाली भूमि पर पार्क तैयार करने के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में निगमायुक्त मती प्रीति यादव, एस.डी.एम. अधारताल पंकज मिश्रा, उपायुक्त सह नोडल अधिकारी NACP नगर निगम जबलपुर संभव अयाची, तहसीलदार, अधारताल सु जानकी उईके, जी.आई.एस. एक्सपर्ट बालेन्द्र शुक्ला, सहायक नोडल अधिकारी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अभिनव मिश्रा, सहा. अर्बन प्लानर, नगर निगम जबलपुर सु अनमोल संस्कृति एवं टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग कार्यालय जबलपुर आर.एस. पटेल उपस्थित रहे। जी.आई.एस. एक्सपर्ट स्मार्ट सिटी जबलपुर बालेन्द्र शुक्ला द्वारा वर्तमान में Bio-Remediation कार्य के संबंध में एवं सहा. अर्बन प्लानर सु अनमोल संस्कृति द्वारा प्रस्तावित पार्क हेतु तैयार की गई डिजाइन का प्रस्तुतीकरण किया गया।

बैठक में कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा रिक्त होने वाली भूमि पर विभिन्न प्रकार के संभावित योजनाओं पर चर्चा की गयी। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि इसके संबंध में दैनिक समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से शहर के नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किये जायें। राजस्व विभाग के उक्त स्थल का सीमांकन शीघ्र किये जाने के लिये निर्देशित किया गया साथ ही टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग से चयनित भूमि के भू-उपयोग एवं उस पर किये जाने वाली गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया।

व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सौंपे दायित्व

जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पुस्तक मेला की व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को दायित्व सौंपकर कहा कि पुस्तक मेला को भव्य व आकर्षक बनायें। पुस्तक मेला के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ज्ञात हो कि यह मेला 25 मार्च से 5 अप्रैल तक शहीद स्मारक प्रांगण में शनिवार और रविवार को दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं शेष दिवसों में शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया जायेगा। कलेक्टर सक्सेना ने मेले की संपूर्ण व्यवस्था के लिये जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया है। टेंट व पंडाल व्यवस्था के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेएटीसीसी हेमंत सिंह को, मेला स्थल का लेआउट व स्टॉल के लिये कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शिवेन्द्र सिंह को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग एनएस रघुवंशी और सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास मनीष सेठ को दायित्व सौंपे है। इसी प्रकार डाइट प्राचार्य सुधीर उपाध्याय व डीपीसी योगेश शर्मा को पुरानी पुस्तकें प्राप्त कर उनके सेट बनवाने एवं बुक बैंक की समस्त जिम्मेदारी तथा एनसीईआरटी की पुस्तकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने के लिये, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक विनीत रजक को दुकानदारों से समन्वय एवं कैरियर काउंसलिंग कराने, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक आशीष दीक्षित को स्वयं सेवी संगठनों से समन्वय करने के निर्देश दिये हैं। एसडीएम अधारताल और पंकज मिश्रा को मेला स्थल की संपूर्ण साफ-सफाई, मैदान का समतलीकरण, मंच एवं कंट्रोल रूम की संपूर्ण व्यवस्था, आस्थाई टॉयलेट व मेला स्थल पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराने का नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा उनके सहयोगी अपर आयुक्त नगर पालिक निगम आरपी मिश्रा होंगे। प्रोटोकॉल की समस्त व्यवस्थाओं के लिये जिला सत्कार अधिकारी ऋषभ जैन को दायित्व सौंपा गया है। मेला स्थल पर दुकानों की 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी, यातायात व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर को एवं मंच व्यवस्था सभी अशासकीय विद्यालयों से समन्वय, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशकों से समन्वय व शिकायतों के निराकरण के लिये जिला शिक्षा अधिकारी व डीपीसी का दायित्व सौंपा गया है। पुस्तक मेला की आय-व्यय के संपूर्ण लेखा रखने के लिये जिला कोषालय अधिकारी सु विनायिका लकरा, मेले में संचालित हेल्प डेस्क एवं समस्त तकनीकी कार्य के लिये जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस चित्रांशु त्रिपाठी तथा मेले स्थल पर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था एवं फुड स्टॉल पर विक्रय होने वाली खाद्य सामग्री की जांच के लिये सीएमएचओ एवं जिला खाद्य अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है।

विवाद सुलझाने गए व्यक्ति पर ही आरोपियों ने किया हमला

माढ़ोताल में चाकू व लाठी से हमला कर हत्या

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अतंर्गत दो पक्षों के बीच चल रहे एक विवाद में मोहल्लें के ही आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू और लाठी से हमला कर एक 45 वर्षीय व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। घटना में घायल व्यक्ति को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है आरोपी अभी फरार है। माढ़ोताल पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चू राम नुनिया घर पर खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए निकला था। मोहल्लें में रहने वाले रजीव, राजा चौधरी, अंकित चौधरी, मुकेश चौधरी और उनके अन्य साथियों के द्वारा विवाद किया जा रहा था जहां बच्चू राम सुलह कराने पहुंच गया। इस दौरान आरोपी उससे विवाद करने लगे, और उस पर ही लाठी व चाकू से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। का विरोध करने बच्चू राम मौके पर पहुंचे थे जहां क्षेत्र के बदमाशों ने बच्चू राम से ही विवाद करना शुरू कर दिया और बदमाशों के द्वारा लाठी और चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया यहां मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत ही माढ़ोताल थाना पुलिस को सूचना दी जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चू राम को तुरंत ही जिला विक्टोरिया अस्पताल भिजवाया गया लेकिन उसकी अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई जहां पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 109, 351(3), भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

औरिया मटर मंडी की दुकानों के आवंटन पर रोक

हाईकोर्ट ने मांगा सभी निविदाओं का ब्यौरा

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर मटर मंडी को औरिया में शिफ्ट किये जाने के मामले में गम्भीरता दर्शाई। जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की कोर्ट ने कहा कि आगामी सुनवाई तक औरिया मंडी में दुकाने आवंटन की निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर 24 मार्च को 24 फरवरी के विज्ञापन के तहत प्राप्त निविदाओं का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया जाए।

जबलपुर थोक सब्जी मंडी व्यापारी संघ की ओर से याचिका दायर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने याचिकाकर्ता व्यापारियों की ओर से कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए जबलपुर की मटर मंडी कृषि उपज मंडी से हटाकर औरिया शिफ्ट की जा रही है। यह कुछ बड़े मटर व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।जबकि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन में सब्जी व फल सबके लिए उपमंडी खोलने का प्रावधान किया है। तर्क दिया कि सब्जी व फल मंडी शहर में और मटर मंडी बाहर करने से यहां के छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान पहुँचेगा। मंडी में70 दुकानों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। जबकि छोटे सब्जी व्यापारी सैकड़ों की संख्या में हैं। उन्होंने आग्रह किया कि कोर्ट उक्त निविदा के क्रियान्वयन पर रोक लगाए। मटर मंडी को अन्यत्र न हटाया जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त दुकानों की निविदा को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी।

रानीताल के पास स्थित जमीन को विकसित करने में नागरिकों से सकारात्मक सुझाव लें : कलेक्टर

जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में रानीताल स्टेडियम के पास स्थित जमीन को नये प्रोजेक्ट के साथ शहरी सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर सक्सेना ने कहा कि उक्त स्थल का सर्वप्रथम सीमांकन कर फेंसिंग करायें। प्राथमिक रूप से उन्होंने कहा कि यहां के डंप कचरे को हटाकर सिटी फॉरेस्ट विकसित कर वॉटर बॉडी को पुनर्जीवित करना है। साथ ही इस स्थान पर कुछ अच्छा नया प्रोजेक्ट लाकर रोजगार व व्यापार को बढ़ावा देने वाले कार्य किये जायें। नगर के अधिकारियों ने कहा कि उक्त स्थल पर एक व्यवस्थित तथा आकर्षक पार्क बनाया जायेगा। जहां शहर के प्रतिष्ठित लोगों के स्टेच्यु भी होंगे। फाउंटेन, स्केटिंग रिंग, बिलियर्ड क्लब, दर्शकों के लिये ओपन टेरिस प्वाइंट, घास के मैदान, पोंड, रोज गार्डन तथा केफे होगा, जो रानीताल झील से लगा होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रानीताल लेक में बोटिंग कराने की कार्य योजना पर भी कार्य किया जा सकता है। कलेक्टर सक्सेना ने कहा कि उक्त जमीन को विकसित करने में शहर के गणमान्य नागरिकों से सकारात्मक सुझाव लें ताकि सभी के सुझावों से एक बेहतर प्रोजेक्ट आम जनता के बीच आये। बैठक में नगर निगम कमिश्नर मती प्रीति यादव, आधारताल एसडीएम पंकज मिश्रा, तहसीलदार सु जानकी उइके सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे।

बजट में खास

5500
करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के लिए

4686
करोड़ रुपए बजट में सीएम राइज को आवंटित

4400
करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित

4050
करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटित

2000
करोड़ रुपए निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किए गए आवंटित

1550
करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए गए आवंटित

1150
करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन

1100
करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के अंतर्गत किए गए आवंटित

1100
करोड़ रुपए 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु)

1071
करोड़ रुपए अमृत 2.0 के अंतर्गत किए गए आवंटित

1000
करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 के लिए

850
करोड़ रुपए मेट्रो रेल के अंतर्गत आवंटित किए गए

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संतुलन के लिये गत एक वर्ष में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के सफल आयोजन किए हैं। माह फरवरी, 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 89 एमओयू हस्ताक्षरित हुए तथा रुपए 26 लाख 61 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके फलीभूत होने से 21 लाख से अधिक नवीन रोजगार सृजन संभावित हैं

39 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से 3 लाख से अधिक रोजगार सृजन होंगे

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संतुलन के लिये गत एक वर्ष में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के सफल आयोजन किए हैं। माह फरवरी, 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 89 एमओयू हस्ताक्षरित हुए तथा रुपए 26 लाख 61 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा

निवेश प्रस्तावों के फॉलो-अप के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना

1 लाख किलोमीटर सड़कें व 500 रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि अगले 5 वर्ष में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना 'क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण' शुरू की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ऐसे गांव, जो मुख्य सड़क से दूर हैं या वहां तक सड़क उपलब्ध नहीं हैं, वहां 'मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना' प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उज्जैन-जावरा 4-लेन का होगा निर्माण, मुंबई कॉरिडोर से जुड़ेगी

वित्त मंत्री ने कहा कि रोड नेटवर्क, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी अनेक परियोजनाओं के साथ प्रदेश अधोसंरचना विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना एवं इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। उज्जैन-जावरा 4-लेन के निर्माण से उज्जैन, इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र, मुंबई-दिल्ली 8-लेन कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। 1 हजार 692 करोड़ की अनुमानित लागत के उज्जैन-इंदौर 6-लेन मार्ग का भूमि पूजन हो चुका है।

सड़क निर्माण में नवीन तकनीक

प्रदेश में सड़क निर्माण में नवीन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से फुल डेप्थ रिक्लेमेशन पद्धति द्वारा ग्वालियर, गुना, दतिया जिलों में सड़कों का निर्माण प्राथमिक तौर पर प्रारंभ किया गया है। जेट पैचर, वेगासिटी पैचर, इंफ्रारेड, माइक्रोसरफेसिंग पद्धति से सड़कों की मरम्मत, लाइट-टॉपिंग तकनीक से सीमेंट कांक्रीट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। एक नवीन योजना 'निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

10 हजार स्टार्टअप स्थापित होंगे

सरकार टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को प्रोत्साहित कर रही है। एनिमेशन, विजुअल इफैक्ट, कॉमिक्स, सेमी कंडक्टर निर्माण इकाईयों तथा ड्रोन प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए नवीन नीतियां तैयार की गई हैं। 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' के अंतर्गत इस वर्ष 5 हजार 675 लाभार्थियों को लगभग रुपए 378 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की है, जिसके अंतर्गत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।

रीजनल कनेक्टिविटी योजना से हवाई सफर आसान होगा

शिवपुरी विमानतल के रूप में विकसित होगा

प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे मप्र के शहरों और देश के महत्वपूर्ण शहरों के मध्य आवागमन शीघ्र तथा सुगम होगा। रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के अंतर्गत छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ एवं उज्जैन हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है। दतिया हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया गया है। शिवपुरी हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया जाएगा। रीवा विमानतल, प्रदेश का छठवां वाणिज्यिक विमानतल बनाया गया है। ग्वालियर विमानतल को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया जा चुका है। उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई कनेक्टिविटी के रूप में विस्तारित किया जाएगा।

युवाओं के लिए कई योजनाएं

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 500 करोड़, एडीबी परियोजना (कौशल विकास) के अंतर्गत 270 करोड़, स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता के अंतर्गत 247 करोड़, पोलीटेक्निक संस्थाएं के अंतर्गत 232 करोड़, मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत 150 करोड़, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22 नए आईटीआई खोले जाएंगे

प्रत्येक संभाग में मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य

जगदीश देवड़ा ने बताया कि आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर एवं आईआईटी दिल्ली के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों हेतु प्रयोगशालाओं की विजिट, लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स के उपयोग, निःशुल्क इंटर्नशिप तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध हुए हैं। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैम्पस स्थापित किया जा रहा है। आगामी पाँच वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आईआईटी के स्वरूप की मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का भी हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष आईटीआई विहीन 22 विकासखंडों में नवीन आईटीआई प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आईटीआई की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल 1 लाख 21 हजार सीटों की हो गई है। विभिन्न आईटीआई में जनजातीय एवं परंपरागत कौशल, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित पाठ्यक्रम तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय आईटीआई देवास, छिंदवाड़ा एवं धार में ग्रीन स्किलिंग से संबंधित पाठ्यक्रम, जैसे सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, प्रारंभ किए गए हैं।

हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे सर्व-सुविधायुक्त स्टेडियम

वित्त मंत्री ने कहा कि 'खेलो इंडिया योजना' के तहत, उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 'खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर' स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की अधोसरंचना, उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध हैं। वर्तमान में 18 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक एवं 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त 09 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 05 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक तथा 56 खेल स्टेडियम शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'सीएम युवा-शक्ति' योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सर्वसुलभ एवं सर्वसुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना हेतु रुपए 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना 'परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन' अंतर्गत प्रदेश के परम्परागत खेल यथा कबड्डी, खो-खो, गिल्ली-डंडा, शतरंज, कुश्ती, तीरंदाजी, गदा, पिट्ठू, कंचे आदि की प्रतियोगिताओं का आयोजन समस्त विकासखंडों में भारत सरकार एवं एनआईएस पटियाला के तत्वाधान में किया जावेगा।

'क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना' के लिए 100 करोड़

'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं लगभग 5 हजार 200 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत अब तक 8 हजार 631 ग्रामों को, 19 हजार 472 किलोमीटर लंबाई की सड़कें निर्मित कर, बारहमासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। कुछ मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा वर्षाकाल में जलमग्न हो जाने से बारहमासी सड़क संपर्क प्रभावित होता है, अतः एक नवीन योजना 'क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना' प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिए 16 हजार 436 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिए 16 हजार 436 करोड़ का प्रावधान

4 हजार 251 करोड़ के रेलवे ओवर ब्रिज बन रहे

नागरिक सुविधाओं एवं औद्योगीकरण में वृद्धि के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2024-25 में 3 हजार 750 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा उन्नयन, 850 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 42 पुलों तथा रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। रेल्वे क्रॉसिंग पर यातायात बाधित होने से समय एवं ईंधन के अपव्यय को रोकने हेतु रेल्वे ओवर ब्रिज (आरओबी) एवं रेल्वे अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण कार्य रेल्वे से समन्वय कर प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। प्रदेश में 4 हजार 251 करोड़ लागत के कुल 116 नवीन रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में एक लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाने का लक्ष्य है। इसी तरह प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 500 रेल ओवर ब्रिज एवं फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे।

वित्त वर्ष 2024-25 में 42 पुलों तथा रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण पूर्ण किए गए हैं

पीएम ऊषा के तहत 565 करोड़ दिए

बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संकाय शुरू किए गए

प्रदेश में 'स्वामी विवेकानंद युवा-शक्ति मिशन' प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं की विशिष्ट क्षमताओं का संवर्धन तथा दक्षता उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र में 73 विश्वविद्यालय एवं लगभग 1 हजार 400 महाविद्यालय हैं। 'प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के तहत प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इन कॉलेजों में बहुसंकायी पाठ्यक्रमों और नवीनतम विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरूआत को प्रदर्शित करती है। राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए खरगोन, गुना और सागर में तीन नए शासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए 133 नए भवनों के निर्माण तथा 192 महाविद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी प्रचलित हैं। पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों तथा 27 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान तथा महिलाओं के समानता और समावेशन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल राशि रुपए 565 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं।

बजट पर इनका नजरिया

युवाओं-महिलाओं के लिए उत्साहजनक बजट

अरुणा सिंह
को-फाउंडर
एन्साज क्रिएशन

इस बार सरकार का बजट युवा और महिलाओं पर केंद्रित रहा है। शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही पुराने टैक्स में कोई वृद्धि की गई, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रावधान बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की पढ़ाई को 73 विश्वविद्यालयों में शामिल करना एक दूरदर्शी कदम है, जो युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करेगा। सरकार लगातार स्टार्टअप्स और युवाओं को अपने आइडिया पर काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत 10 लाख रुपए से की थी और आज हमारा वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपए है। एन्साज क्रिएशन एजुकेशनल टॉयज का निर्माण करता है, जिससे बच्चे खेल-खेल में सीख सकें, उनका मानसिक विकास हो और वे नई स्किल्स हासिल कर सकें। हम लगातार नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। साथ ही, स्कूलों तक इन उत्पादों को पहुंचाने के लिए भी प्रयासरत हैं। अब तक 50 से अधिक प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। सरकार से हमें इन्क्यूबेशन स्पेस और अन्य सहयोग भी मिला है, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। यह बजट निश्चित रूप से युवाओं, स्टार्टअप्स और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का कार्य करेगा।

सरकार के बजट में सभी वर्गों का ध्यान

कार्तिक साहू
फाउंडर एवं डायरेक्टर
रेंटोजो डॉट कॉम

मैंने रेंटोजो डॉट कॉम की शुरूआत सोशल मीडिया के माध्यम से की थी और आज कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 35 से 40 लाख रूपए है। कंपनी रेंटल प्रापर्टी पर काम करती है। हमें सरकार की ओर से ऑफिस और सलाहकारों की बेहतर व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के साथ ही युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर निर्णय किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का बजट सभी वर्गों-युवा, महिला, उद्यमी, किसान और गरीब-को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही पुराने टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई। इसका मतलब है कि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही, किसी भी वस्तु या सेवा पर छूट की घोषणा भी नहीं हुई, जिससे कीमतों में कमी की उम्मीद भी नहीं है। शिक्षा में एआई की पढ़ाई शुरू करना और 73 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल करना एक दूरदर्शी कदम है। यह युवाओं को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार कर सकता है। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए और जनजातीय बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूलों में 1017 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वागत योग्य है।

युवाओं और रोजगार के लिए योजनाएं

1000 करोड़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

1000 करोड़ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना

03 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगा रोजगार

बजट में युवाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान निजी क्षेत्र में 3 लाख रोजगार का किया गया है। ये रोजगार नए विकसित हो रहे 39 औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेंगे। छात्रों के लिए पहले से चल रही लैपटॉप योजना के लिए 220 करोड़ और साइकिल के लिए 215 करोड़ का प्रावधान किया है। छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 803 करोड़ तथा सीएम राइज विद्यालयों के लिए 1 हजार 617 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। इसी के साथ प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा।

बुजुर्गों को क्या-क्या मिला?

वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना में, प्रारंभ से अब तक 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन निर्धारण की ऑनलाइन प्रणाली के अन्तर्गत पेपरलेस व्यवस्था लागू है, वर्तमान पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को केन्द्रीकृत तथा फेसलेस किया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसी भी स्थान अथवा कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन निर्धारण की कार्यवाही केन्द्रीकृत कार्यालय में पदस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा संपादित हो सकेगी।

वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ का प्रावधान

पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को केंद्रीकृत तथा फेसलेस किया जाएगा

बजट में खास

महिलाओं को अटल पेंशन से जोड़ेंगे

लाड़ली बहनों को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। अटल पेंशन योजना से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा।

फसल बीमा के लिए 2 हजार करोड़ रुपए

धान उपार्जन के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए 850 करोड़ का प्रावधान है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरंतर रखा गया है. इस मद में 19 हजार 208 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए इस बार 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

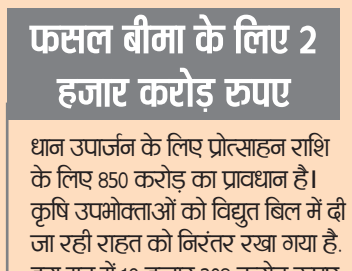

प्रदेश में खुलेंगे 56 खेल स्टेडियम

प्रदेश में 18 अंतर्राष्ट्रीय स्तर हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 56 खेल स्टेडियम शीघ्र उपलब्ध होंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम बनेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 23 हजार 535 करोड़ आवंटित

मप्र में एमबीबीएस की बढ़ाई 400 सीटें खुलेंगे और 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 23 हजार 535 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में रुपए 2 हजार 992 करोड़ अधिक है। इस दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने नई योजना सी.एम. केयर का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को नजदीकी अस्पतालों में ही कैथ लैब और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बुधवार को 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का अपना दूसरा बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 23 हजार 535 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में रुपए 2 हजार 992 करोड़ अधिक है। इस दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने नई योजना सी.एम. केयर का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को नजदीकी अस्पतालों में ही कैथ लैब और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, आयुष्मान योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 2 हजार 39 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 17 चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 2 हजार 575 सीट्स और स्नातकोत्तर के लिए एक हजार 337 सीट्स हैं। इस वित्तीय वर्ष में नीमच, मंदसौर और सिवनी में नए शासकीय चिकित्सालय कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर शासकीय व निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस की 400 व स्नातकोत्तर की 252 सीट्स बढ़ाई गई हैं। प्रदेश में 1 हजार संजीवनी एम्बुलेंस और 1 हजार 59 जननी एम्बुलेंस संचालित हैं।

आयुष्मान योजना के लिए 2025-26 के लिए 2 हज़ार 39 करोड़ का प्रावधान

गंभीर बीमारियों के इलाज सुविधाएं उपलब्ध होंगी

50 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 11 नए आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना की जानी है। प्रदेश में पन्ना, गुना, भिण्ड, श्योपुर तथा शुजालपुर में 50 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बड़वानी में 30 बिस्तरीय अस्पताल, बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुष महाविद्यालयों और 4 जिला आयुष कार्यालयों के भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित आयुष संस्थाओं एवं शिविरों के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को उपचार दिया गया है।

600 नए विद्यालय खोले जाएंगे

तकनीकी शिक्षा व अनुसंधान पर भी किया पूरा फोकस

मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों और योजनाओं का खाका पेश किया गया है। बजट में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करना और नई तकनीकों से जोड़ना है। बजट में सीएम राइज स्कूल योजना को विस्तार दिया है। योजना के तहत अब तक 275 विद्यालय खोले जा चुके हैं और वर्ष 2025-26 तक इन विद्यालयों में परिवहन सुविधा भी शुरू की जाएगी।

इसके अलावा, पीएमश्री योजना के तहत 780 विद्यालयों में आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी सरकार ने बड़ा एलान किया है। वर्ष 2024-25 में 3,259 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 19,362 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब तक 2,383 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 600 नए विद्यालयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उच्च शिक्षा को मिलेगी नई दिशा

प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार किया गया है। वर्तमान में राज्य में 73 विश्वविद्यालय और 1,400 से अधिक महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' योजना के तहत प्रत्येक जिले में महाविद्यालय को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

22 नए आईटीआई खुलेंगे

22 नए व्यवसायों में आईटीआई शुरू करने की मंजूरी दी गई है। आईटीआई संस्थानों की संख्या बढ़कर 958 हो जाएगी और 1.21 लाख सीटें उपलब्ध होंगी आईटीआई संस्थानों में जनजातीय एवं परंपरागत कौशल, जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। देवास, छिंदवाड़ा और धार में सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे आधुनिक ट्रेड भी शुरू किए हैं।

2047 तक मप्र का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगा

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। ये बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का है। यह मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का दूसरा वार्षिक बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2047 तक मध्यप्रदेश का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य है। इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है।

- आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ राशि
- जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां
- श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान

बजट की प्रमुख और बड़ी घोषणाएं

- अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत 47 हजार 295 करोड़ का प्रावधान
- पेंशन के लिए 4 हजार 66 करोड़, गरीबों के लिए 7132 करोड़
- नागरिकों के लिए राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा
- लाड़ली बहनों को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा
- महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना अंतर्गत 223 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी

- गीता भवन बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
- खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ का प्रावधान
- आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया।
- जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा, 200 करोड़ का बजट रखा गया।
- अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 32 हजार 633 करोड़ का प्रावधान।

बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे

जनजातीय कल्याण और कुपोषण मुक्ति का रखा विशेष ध्यान

बजट 2025-26 में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना के तहत 53,000 से अधिक आवास बनाए गए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे, जिससे 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। प्रदेश में 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसके लिए 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा, जो युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 900 से अधिक आईटीआई संस्थान होंगे, जो युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण देंगे।

अधोसंरचना होगी मजबूत

- मप्र सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- एफ टाइप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के अनुरक्षण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अंतर्गत 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे मध्य प्रदेश में ग्रामीण पहुंच मार्ग आसान हो जाएंगे।
- मप्र सड़क विकास निगम (एनडीबी) के अंतर्गत 1450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (एडीबी) के अंतर्गत 1315 करोड़।
- केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1150 करोड़।

23 हजार प्राथमिक स्कूल भी खोले जाएंगे

सरकार राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 23,000 प्राथमिक स्कूल, 6,800 माध्यमिक स्कूल और 1,100 हाई स्कूल खोलेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेज में 400 सीटें बढ़ाई जाएंगी। सरकार नए 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेगी। बजट में सरकार का फोकस आर्थिक वृद्धि तेज करने के उपायों पर दिखा। वित्तमंत्री ने कहा कि 2047 तक सरकार ने राज्य की जीडीपी को 250 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने इस बार बजट का आकार 15 फीसदी बढ़ाया है। सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस करेगी। सरकार का टारगेट राज्य में 39 औद्योगिक क्षेत्रों के जरिए 3 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करने पर होगा।

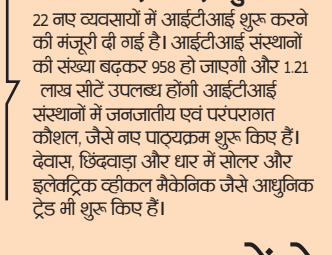

बजट पर इनका नजरिया

प्रतिस्पर्धा ज्यादा लेकिन पीछे नहीं हटना है बल्कि मुकाबला करना है

प्रीति सेठ
संचालक
एमवीएल
एंटरप्राइजेज

मुझे शुरू से ही कुछ ना कुछ करने का शौक था और मेरे पति मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि तुम बॉडी बेल्ट बनाने का काम शुरू कर सकती हो क्योंकि आजकल लोगों को गले में, हाथ में, पैर में या कमर में दर्द की समस्या बनी ही रहती है। इसके लिए अच्छी क्वालिटी का बेल्ट मिलना भी बेहद जरूरी है, तो हमने आज से 6 साल पहले अपना स्टार्टअप एमवीएल एंटरप्राइजेज शुरू किया, जिसमें हम बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स के लिए बेल्ट बनाते हैं। उन्होंने कहा की शुरूआत में मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा क्योंकि कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पाते थे लेकिन फिर मैं अपने प्रोडक्ट में चेंज करती गई और आज हम काफी अच्छे से इस्टेबिलिश हो चुके हैं। मेरा मानना है कि जब भी आपको स्टार्टअप शुरू करते हो तो उसमें उतार चढ़ाव लगे ही रहते है, कंपटीशन ज्यादा होती है लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पीछे नहीं हटाना है।

किसानों की आय दोगुना करने की गारंटी बजट से गायब हो गई

इरफान जाफरी
प्रमुख किसान
जागृति संगठन

आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट से प्रदेश के किसानों को बहुत उम्मीद थी। किसान सरकार की गारंटी के हिसाब से अपना अनुमान लगा रहे थे कि किसान की आय दोगुना करने के लिए कोई स्कीम लाई जाएगी। इसके अलावा किसान अपनी आमदनी को लेकर भी कुछ बेहतर होने की उम्मीद संजोए हुए थे। ऐसे ही सपनों के साथ किसानो को आशा थी कि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलेगा। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मद में कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है। बेहतर होता यदि किसानों की आय बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाता तो किसानों की माली हालत में सुधार होता।

एमएसपी तय करने से परहेज दोगुनी आय भी नहीं की गई

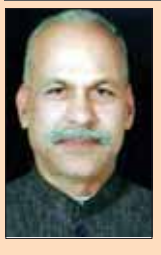

शिवकुमार शर्मा
'कक्काजी'
अध्यक्ष, किसान
मजदूर महासंघ

किसानों की फसल का एमएसपी तय करने से तो सरकार परहेज कर रही है। ऊपर से किसानों को धोखा देते हुए कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। यह सरकारी धोखा है। सरकार बजट के प्रावधानों के हिसाब से किसानों की आय को 2014 तक लाने की तैयारी कर रही है। कानून के तहत मंडियों का व्यापारीकरण किया गया है। एमएसपी को कानून के दायरे में लिया जाना चाहिए। यह सरकार किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी।

आज रात होगा होलिका प्रतिमाओं का दहन

महंगाई की मार के बीच त्यौहार की उमंग फीकी

जबलपुर।

असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व होलिकोत्सव पर गुरुवार की रात होलिका प्रतिमाओं का दहन किया जाएगा। रंग, उमंग और मस्ती से भरे इस त्यौहार को मनाने की तैयारियों में लोग जुट गये हैं। घर-घर पकवान बन रहे हैं। बच्चे रंग और पिचकारी के अलावा तरह-तरह के मुखौटे, टोपियां लेकर प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर होलिका प्रतिमाओं की स्थापना बुधवार को ही कर दी गई, वहीं अनेक स्थानों पर गुरुवार को ही होलिका प्रतिमाएं बिठाई जाएंगी और रात्रि के प्रथम पहर तक होलिका दहन कर दिया जाएगा। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर बाजारों में अच्छी खासी रौनक रही। रंग-गुलाल पिचकारियों, मेवा मिष्ठानों की दुकानों पर लोग खरीददारी करते देखे गये। शनैः-शनैः त्यौहार की भयावहता के कारण लोगों का उत्साह और उमंग घटता जा रहा है। रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। पुलिस में आज होलिका दहन की रात और कल धुरेड़ी के दिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये। एसएएफ बटालियन की तीन कंपनियां जबलपुर में आ चुकी हैं। शराबखोरी और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इस साल होलिका दहन पर भद्रा पड़ने के कारण शास्त्रों के मुताबिक होलिका दहन रात 10 बजकर 44 मिनिट के बाद भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही शुभ मुहूर्त में होगा उसके बाद दूसरे दिन शुक्रवार को रंग अबीर खेला जाएगा।

होली की पौराणिक मान्यता

बहरहाल होली के त्यौहार की पौराणिक मान्यता यह है कि राजा हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी दानव था। लेकिन उसका पुत्र भक्त प्रहलाद एक धार्मिक और न्यायप्रिय था। राजा हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र का आचरण पसंद नहीं था। वह उसे भी दानव बनाना चाहता था। ऐसी मान्यता है कि भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के अनन्य भक्त थे और तमाम अत्याचार करने के बाद भी जब राजा अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को दानवी शक्ति से प्रभावित नहीं कर सके तो उन्होंने अग्नि में भस्म नहीं होने का वरदान प्राप्त अपनी बहन होलिका की गोद में अपने पुत्र प्रहलाद को बिठाकर आग के हवाले करने की कोशिश की। लेकिन ईश्वर की कृपा से वरदान का दुरूपयोग करने वाली होलिका तो आग में धूं-धूंकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गये। तभी से आसुरी शक्ति पर देवीय शक्ति के विजय प्रतीक इस पर्व पर होलिका प्रतिमा का दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन सारी बुराईयों को समाप्त कर दूसरे दिन रंग-गुलाल के साथ गले मिलकर गिले शिकवे भुलाने का संदेश यह पर्व देता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से असामाजिक तत्वों, शराबियों ने इस पर्व के मायने ही बदल दिये हैं। इसलिए पुलिस को इस त्यौहार में खासी सख्ती करनी पड़ती है।

सिटी बंगाली क्लब में दोल उत्सव आज

होली के एक दिन पूर्व पूर्णिमा की रात्रि में मनाए जाने वाला दोल उत्सव सिटी बंगाली क्लब में 13 मार्च गुरुवार रात्रि 7.30 बजे से आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सभी बंगभाषी एकत्र होकर इस दिन होने वाले पूर्णिमा पूजा, होलिका दहन नेडा पोडा कार्यक्रम में शामिल होंगे साथ ही पारंपरिक गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। दोल उत्सव को लेकर बंगभाषियों में उत्साह देखा जा रहा है पूरे प्रांगण में आकर्षक सजावट की गई है।

रंगाभरण थिएटर ग्रुप META के लिए चुना गया

जबलपुर। अक्षय सिंह ठाकुर द्वारा लिखित और निर्देशित यह नाटक 15 मार्च को दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित कमानी ऑडिटोरियम में मंचित होगा, जहां हमारे बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ।

META (Mahindra Excellence in Theatre Awards) भारत का एक सबसे प्रतिष्ठित थिएटर अवार्ड है, जिसे 2006 में महिंद्रा ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय थिएटर के उत्कृष्ठ नाटकों को सम्मानित करता है और थिएटर कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है।

इस वर्ष META के लिए पूरे देश से 367 प्रविष्टियाँ आई थीं, जिनमें से सिर्फ़ 10 नाटकों का चयन किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है रंगाभरण थिएटर ग्रुप जबलपुर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

नर्मदा पंचकोषी परिक्रमा आज

जबलपुर। हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट से प्रत्येक पूर्णिमा को निकल जाने वाली नर्मदा पंचकोषी परिक्रमा 13 मार्च फागुन पूर्णिमा पर प्रात 6:00 बजे संत महात्माओं के सानिध्य में निकाली जाएगी। बद्रीनाथ धाम से पूजित गोमती चक्र का वितरण होगा एवं विशाल भंडारे का आयोजन के साथ समापन होगा। उपस्थिति की अपील नर्मदा महाआरती के संस्थापक नर्मदा पंचकोषी परिक्रमा के अध्यक्ष डॉ सुधीर अग्रवाल संरक्षक श्रीमती सुषमाशंकर पटेल मनमोहन दुबे श्याम मनोहर पटेल विनोद दीवान मनोज गुलब्बानी कैलाश विश्वकर्मा विशाल पड्या आदि ने की है।

महिलाओं के उत्थान के लिए यूनियन प्रीमियर संकल्पित

जबलपुर। दयूनियन बैंक प्रीमियर शाखा के तत्वधान में महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी महिलाओं का सम्मान किया गया, एवं समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम में नारी शक्तियों ने समाज और राष्ट्र के उत्थान में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर व्याख्यान दिया साथ ही चीफ मैनेजर अमित कुमार ने महिलाओं से संबंधित सभी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी साझा किए एवं सुगम बैंकिंग उपलब्ध कराने की बात कही साथ ही उपस्थित महिलाओं एवं अतिथियों ने सम्मान कार्यक्रम आयोजन की सराहना किए। प्रमुख रूप से सीएमएचओ डॉ बबिता खरे, केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य अंशु त्यागी, चीफ मैनेजर अमित कुमार, आरडीओ मनाली सोनटके, एलडीएम बृजेश श्रीवास्तव,आरसेटी डायरेक्टर शिवेंद्र कुमार, साहित्य क्षेत्र से शिवशंकर मिश्रा ' सरस ' एवं यूनियन बैंक प्रीमियर शाखा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

गुंजन का रसरंग महोत्सव आज

जबलपुर। गुंजन कला सदन द्वारा 32 वर्षों से निरंतर जारी "रसरंग महोत्सव" इस वर्ष अनेक नए आकर्षण के साथ होलिका दहन की संध्या 13 मार्च को शाम 6 बजे से शहीद स्मारक भवन में आयोजित है । समारोह में सभी अतिथियों और दर्शकों को आयोजकों द्वारा दूल्हा बनाकर सम्मानित किया जाता है । गुंजन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. आनंद तिवारी ने बताया कि इस समारोह में नृत्यगुरु मोती शिवहरे के निर्देशन में मनभावन होली गीतों पर आकर्षक नृत्यों के साथ ही ख्यातिलब्ध हास्य कलाकार के. के. नायकर हास्य के धमाके करेंगे । संजय जैन "कीपी" एवं हिमांशु तिवारी के अनुसार इस अवसर पर दोनों ही कलाकारों को "लाइफ टाइम एचीवमेंट अवॉर्ड" प्रदान किया जाएगा ।

अमृत मित्र बनी महिलाएं जांचेंगी पानी की गुणवत्ता

जबलपुर। अमृत 2.0 योजना के तहत अमृत मित्र अंतर्गत नगर निगम के ललपुर जल शोधन संयंत्र में स्व सहायता समूह की महिलाओं को जल परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। स्व सहायता समूह की महिलाएं नगरी क्षेत्र में घर-घर जाकर जल परीक्षण का कार्य करेंगी। जिसमें प्रशिक्षण के दौरान नगर निगम से केमिस्ट शुभम गुजराती एवं अमृत 2.0 से सोशल एक्सपर्ट सुधा ठाकुर एवं अमित दांगी जी की सहभागिता रही1

प्रतिदिन परेशान हो रहे हजारों यात्री

रेलवे व बिजली कम्पनी के बीच फंसा सिहोरा स्टेशन रोड के ट्रांसफार्मर हटाने का मामला

सिहोरा। दो विभागों के बीच की आपसी खींचतान का खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है । जिसके चलते हजारों यात्री अपनी जान खतरे में डालकर स्टेशन पहुंचने के लिए मजबूर हैं। यह मामला है सिहोरा रोड रेलवे की सडक का जहां बीच सड़क में खड़े ट्रांसफार्मर से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रेलवे के अधिकारियों का तर्क है कि ट्रांसफार्मर हमारी जगह पर लगा है इससे बिजली कंपनी तत्काल हटाए वहीं दूसरी तरफ बिजली कंपनी का तर्क है कि ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए कंपनी शिफ्टिंग चार्ज जमा करे, तभी ट्रांसफार्मर को हटाया जाएगा।

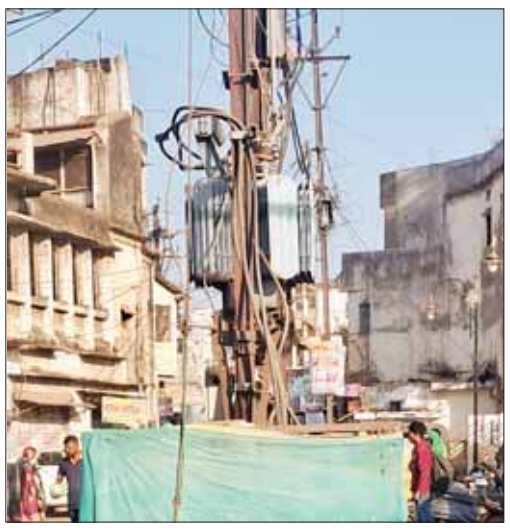

अमृत योजना के तहत हो रहा सौंदर्यीकरण

अमृत भारत योजना के तहत सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के पहले रेलवे के अधिकारियों ने बिजली कंपनी को निर्देशित किया था कि ट्रांसफार्मर हमारी जगह पर लगा हुआ है इसे तत्काल हटाएं। संबंधित ट्रांसफार्मर में रेलवे का कोई भी कनेक्शन नहीं है। बिजली कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं हटाए जाने पर रेलवे ने सड़क को चौड़ा कर दिया और रोड भी बना दी। वहीं बिजली कंपनी का कहना है कि ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए शिफ्टिंग चार्ज रेलवे को जमा करना होगा इसके बाद ही से हटाया जाएगा। ऐसे में दो विभागों की खींचतान के कारण आम यात्रियों को अपनी जान खतरे में डालकर स्टेशन पहुचना पड़ रहा है।

हमेशा बना रहता है रेल यात्रियों का दबाव

सिहोरा रेलवे स्टेशन से सिहोरा, मझौली, बहोरीबंद और ढीमरखेडा से अनेक यात्री अप-डाउन करते हैं। 24 घंटे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव है। ट्रान्सफार्मर बिल्कुल दोनों सडक के बीचों-बीच है इसलिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। भाजपा कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश चौदहा का कहना है कि सडक से ट्रान्सफार्मर अलग करने को लेकर कोई विवाद नहीं है। दोनों विभाग आपसी समन्वयक बनाकर ट्रान्सफार्मर को दूसरी जगह शिफ्ट करे जिससे यात्रियों को को राहत मिले सके।

इनका कहना है

ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जो भी शिफ्टिंग चार्ज निश्चित है उसे रेलवे को जमा करना पड़ेगा इसके बाद ही ट्रांसफार्मर को वहां से शिफ्ट किया जा सकेगा।

अमित कुमार विश्वकर्मा,
डीई मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सिहोरा संभाग

डॉ अखिलेश खंडेलवाल का नगर आगमन पर किया स्वागत

जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. अखिलेश खंडेलवाल के जबलपुर महानगर आगमन पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दीपक नाहर,जिला ग्रामीण के संयोजक ठा. बाबू सिंह, जिला सह संयोजक आशीष शुक्ला ने ढ़ोल-नगाड़ों के साथ फुल माला एवं भाजपा का अंगवस्त्र पहनाकर खंडेलवाल जी का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। जिसमें प्रदेश सह संयोजक दीपक नाहर ने बताया कि डॉ. खंडेलवाल जी सर्वप्रथम विश्राम गृह पहुचे इसके पश्चात जिला जबलपुर ग्रामीण के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजकुमार पटैल जी के आवास पर जाकर उन्हें नये दायित्व की शुभकामनायें प्रेषित कर अनेक विषयों पर चर्चा की। इसके बाद एक भागवत कथा के समापन पर पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड संयोजक पुष्पेंद्र सिंह से उनके निवास पर मिलकर कार्ययोजना की विस्तार पूर्वक चर्चा की। और भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता चेतन शर्मा जी के निवास पर पहुंचकर उनकी माता जी के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। इस अवसर प्रदेश सह संयोजक दीपक नाहर,ठाकुर बाबू सिंह,अनंत पांडे,जगदीश चौहाटेल,आशीष शुक्ला,पुष्पेंद्र सिंह,पुरूषोतम गुप्ता,निखिल ठाकुर,शुभम ठाकुर,अरुण वंशकार,विपिन राजपूत "बंटा", आदर्श राजपूत, अरविंद चढ़ार, कमलेश दुबे सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

श्रीमती श्यामा बाई दुबे- पंजाब बैंक कॉलोनी दमोहनाका निवासी श्रीमती श्यामा बाई दुबे (64) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती रामलली झारिया- शक्तिनगर भोले कुटि के पीछे गुप्तेश्वर निवासी श्री शिवनाथ झारिया की धर्मपत्नी श्रीमती रामलली झारिया (60) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर मोक्षधाम में किया गया।

श्री शत्रुघन सिंह- शिवनगर गढ़ा निवासी श्री शत्रुघन सिंह (68) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती पुष्पा साहनी- नर्मदा रोड निवासी श्री जगदीश साहनी की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा साहनी (79) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर मोक्षधाम में किया गया।

श्रीमती राधा बावरिया- गली नं. 22 सदर निवासी श्री हरि शंकर बावरिया की धर्मपत्नी श्रीमती राधा बावरिया (55) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री राजेश सोनी- शीतलामाई रवि डेरी के पास निवासी श्री रमेश चंद्र सोनी के पुत्र श्री राजेश सोनी (41) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्रीमती कुसुम कुशवाहा- नई बस्ती कजरवारा निवासी श्री विनोद कुशवाहा की धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम कुशवाहा (51) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री शिवनाथ चौधरी- बाबा टोला ठक्कर ग्राम निवासी श्री शिवनाथ चौधरी (48) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्री संतोष कुमार सोनी- स्टेट बैंक कॉलोनी स्नेह नगर निवासी श्री संतोष कुमार सोनी (57) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती कमला देवी रामवानी- झामनदास चौक लालमाटी निवासी श्री रमेश कुमार रामवानी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी रामवानी का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्रीमती उर्मिला तिवारी- पड़वार बरेला निवासी श्री हेतराम तिवारी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला तिवारी (95) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री सोनू प्रजापति- कछियाना द्वारका नगर लालमाटी निवासी श्री सोनू प्रजापति का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

सुश्री सुषमा ठाकुर- पोलीपाथर टंकी नं. 1 के पास निवासी श्री केशव लाल ठाकुर की पुत्री सुश्री सुषमा ठाकुर (53) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती बेला बाई सोनकर- राधाकृष्णन वार्ड निवासी श्री ओम प्रकाश सोनकर की धर्मपत्नी श्रीमती बेला बाई सोनकर (64) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्री वीरेंद्र- बावली लाइन पोलीपाथर निवासी श्री हीरा लाल के पुत्र श्री वीरेंद्र (48) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री नगीनचंद सोनकर- भरतीपुर निवासी श्री नगीनचंद सोनकर (61) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्री संजय खंपरिया- खितौला सिहोरा निवासी श्री संजय खंपरिया का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री मनोज चौधरी- रविदास धाम बाबा टोला निवासी श्री साधूराम चौधरी के पुत्र श्री मनोज चौधरी (34) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्रीमती सिमिया केसरवानी- जाग्रति नगर अमखेरा निवासी श्री फूलचंद केसरवानी की धर्मपत्नी श्रीमती सिमिया केसरवानी (70) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री अर्जुन कोल- नरसिंह मंदिर मदनमहल निवासी श्री दादूराम कोल के पुत्र श्री अर्जुन कोल (43) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया।

श्री अरूण स्वामी- झिरिया सदर निवासी श्री अरूण स्वामी (50) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती संगीता गोलवरकर- द्वारका नगर लालमाटी निवासी श्रीकांत गोलवकर की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता गोलवरकर (81) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया।

डॉ. अनिल गुप्ता- बड़ी ओमती निवासी डॉ. अनिल गुप्ता (75) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

हरिभूमि
निजी/शोक/उठावन, पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि संबंधी संदेश प्रकाशित कराने के लिए
अन्य साइज 40/- प्रति स्क्वायर से.मी.

फिक्स साइज:-	8x4 से.मी.	ब्लैक&व्हाईट	300/-
फिक्स साइज:-	8x4 से.मी.	रंगीन	400/-
फिक्स साइज	10x8 से.मी.	रंगीन	1000/-

सम्पर्क करें विज्ञापन विभाग:- 9303508294, 9407362100

मलेरिया निरीक्षक एवं मलेरिया टेक्नीकल सुपरवाईजर का प्रशिक्षण

जबलपुर। मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के प्रभावी नियंत्रण तथा उपचार से संबंधित नवीन नीति एवं पोर्टल पर डेटा एंट्री के कार्य के संबंध में जबलपुर संभाग के सभी विकासखण्डों के मलेरिया निरीक्षक और मलेरिया टेक्नीकल सुपरवाईजर का एक दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार को डॉ संजय मिश्रा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में भोपाल से आये राज्य स्तरीय दल के सदस्य मती भावना दुबे एवं सुधीश यादव ने तथा सांईटिस्ट एनआईआरटीएच आईसीएमआर गेस्ट फेकल्टी सतेंद्र पांडे ने मलेरिया उन्मूलन एवं आईएचआईपी से संबंधित जानकारी प्रदान की।

होली में भी वेतन के लिए तरसे निगम के ठेका कर्मी

जबलपुर। नगर निगम उद्यान विभाग में 200 कर्मचारी 7-8 वर्षो से काम करते आ रहे है, इन सभी का दो माह से पैमेन्ट ठेकेदार रितेश टंडन द्वारा नहीं दिया जा रहा है, न ही पी. एफ. की राशि दी जा रही है, जिसकी शिकायत नगर निगम आयुक्त को भी की गयी है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्रमिकों को अपना घर परिवार चलाने के लाले पड़े हुए हैं, घर में राशन, पानी, किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली, गैस आदि सभी कर्मचारियों की घर की स्थिति खराब हो गयी है, वर्तमान में होली का पर्व सामने है, और उन ठेका कर्मियो की बात सुनने कोई तैयार नही है। इस अवसर पर महिला पुरूष कर्मचारी मोहम्मद रहमान, कमल, सुन्दर, हिमांशु, गणेश, दशाई, रमेश, रामवती, इत्यादि कर्मचारी मौजूद रहे।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमती रश्मि सक्सेना पति श्री अरविंद सक्सेना निवासी-म.नं. 511, व्हीकल रोड, अंजली कालोनी रिछाई, जबलपुर म.प्र. द्वारा सम्पत्ति मौजा बिलपुर नं.ब. 665 प.ह.नं. 53 रा.नि.मं. बिलपुरा तहसील रांझी नया वार्ड नं. 78 जिला जबलपुर में स्थित डायवर्टेड प्लाट एवं नामांतरण पश्चात खसरा नं. 76 रकवा 0.323 हे. में से प्लाट नं. 11 का कुल रकवा 20 50 1000 वर्गफुट एवं प्लाट नं. 12 का भाग 20 50 1000 वर्गफुट कुल रकवा 2000 वर्गफुट को खरीद करने का सौदा भूमिस्वमी रामचरण कुर्मी पिता मूलचंद कुर्मी की ओर से मख्त्यारआम श्री धीरेन्द्र डागर पिता श्री राम शरण सिंह निवासी-इंद्रा नगर, बिलपुरा रोड, दुर्गा मंदिर के पास, व्ही. एफ. जे. स्टेट, जबलपुर म.प्र. वालो से विक्रय करने का अनुबंध किया गया है, अतः उपरोक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति फर्म या वित्तीय संस्था, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था से कोई आपत्ति हो तो मे मूल दस्तावेज सहित प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में दस्तावेज सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, 7 दिन के बाद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी और दस्तावेजों का पंजीयन करा लिया जावेगा।

जबलपुर, दिनांक- 12.03.2025

भवदीय

राजकुमार श्रीवास्तव (अधिवक्ता)
म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.) कार्यालय-887/बी, गुप्ता होटल के पास शक्ति नगर, गुप्तेश्वर रोड जबलपुर म.प्र. मो. 9300813002

CHANGE OF NAME

I, SYED AAMIR ALI S/O SYED AKHTAR ALI DECLARE THAT MY MINOR SON WAS KNOWN AS SYED AMMAAR ALI, I HAVE CHANGED THE SPELLING OF HIS FIRST NAME AND HENCEFORTH HE SHALL BE KNOWN AS SYED AMMAR ALI S/O SYED AAMIR ALI RESIDENT OF 504, DATTA AND RABRA COMPLEX, NARMADA ROAD, KATANGA CROSSING, GORAKHPUR, JABALPUR (M.P.) 482001

नाम एवं जन्म तिथि सुधार

मैं, कौशल्या पति स्व. स्वामी नादन उम्र लगभग 64 वर्ष निवासी जबलपुर मप्र की निवासी हूँ। यह कि मेरे स्व. पति स्वामी नादन जिनका सर्विस नंबर NK 13843613 है जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 26/04/1985 को हो गई थी जिनकी मृत्यु दिनांक 13/09/2020 को हो चुकी है। यह कि मेरे स्व. पति के पी पी ओ आर्डर में मेरा नाम श्रीमती कौशल एवं जन्मतिथि 11/08/1960 दर्ज हो गई है जो कि गलत व असत्य है। जबकि मेरा सत्य व सही नाम कौशल्या व जन्मतिथि 06/06/1960 है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है। मेरा सत्य व सही नाम कौशल्या व जन्मतिथि 06/06/1960 को मेरे स्व. पति स्वामी नादन के पी पी ओ आर्डर में दर्ज करे। शपथ पत्र दिनांक 12/03/2025 समक्ष पब्लिक नोटरी महोदय जिला जबलपुर मप्र
सत्य नाम एवं जन्मतिथि-कौशल्या (06/06/1960)
असत्य नाम एवं जन्मतिथि-श्रीमती कौशल (11/08/1960)